3 अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध तेज

5 प्रभावशाली नेताओं की श्रेणी में स्थापित

6 संदिग्ध मौत को लेकर कांग्रेस का थाने पर धरना

RNI-MPBIL/2011/39805 DAVP/134083/25

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 17 अंक : 01 प्रति सोमवार, 11 मई 2026 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

सुशासन के दावों पर सवाल, लोधी विवाद ने उजागर किया भाजपा नेताओं का दोहरा चरित्र

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

मध्यप्रदेश की राजनीति में हाल के घटनाक्रम ने एक बार फिर जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही और आचरण पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं। प्रीतम सिंह लोधी से जुड़ा विवाद केवल एक व्यक्ति या परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस व्यापक राजनीतिक संस्कृति को उजागर करता है, जिसमें सत्ता का अहंकार जनसेवा की मूल भावना पर भारी पड़ता नजर आता है। भाजपा स्वयं को "सुशासन" और "जनता ही भगवान है" जैसे नारों के साथ प्रस्तुत करती रही है। लेकिन जब उसी पार्टी के जनप्रतिनिधियों या उनके परिजनों के व्यवहार में संवेदनहीनता और दबंगई सामने आती है, तो यह केवल व्यक्तिगत चूक नहीं, बल्कि उस वैचारिक दावे पर भी सवाल खड़ा करती है, जिसे

पार्टी वर्षों से दोहराती आई है। इस पूरे प्रकरण में जो सबसे चिंताजनक पहलू उभरकर सामने आया है, वह है सत्ता का दुरुपयोग और कानून से ऊपर होने का भ्रम। बताया जा रहा है कि विधायक के परिजन द्वारा जिस प्रकार से आम जनता के साथ व्यवहार किया गया और जिस तरह पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिशें हुईं, वह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि जनता के सेवक होते हैं, शासक नहीं। लेकिन जब "विधायकी की गर्मी" इस कदर सिर चढ़कर बोलने लगे कि आम नागरिकों की सुरक्षा तक खतरे में पड़ जाए, तो यह स्थिति अस्वीकार्य हो जाती है।

विधायक पद से देना चाहिए इस्तीफा

यह पहला मौका नहीं है जब किसी जनप्रतिनिधि या उनके परिवार के सदस्यों पर इस तरह के आरोप लगे हों। समय-समय पर विभिन्न दलों के नेताओं पर ऐसे आरोप सामने आते रहे हैं, लेकिन हर बार यह उम्मीद की जाती है कि संबंधित पार्टी कड़ी कार्रवाई कर एक उदाहरण प्रस्तुत करेगी। इस संदर्भ में हेमंत खंडेलवाल द्वारा जारी किया गया शोकॉज नोटिस एक प्रारंभिक कदम जरूर है, लेकिन यह सवाल बना हुआ है कि क्या केवल नोटिस जारी कर देने से इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लग सकेगा? राजनीति में नैतिकता और मर्यादा केवल भाषणों और प्रशिक्षण शिविरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। भाजपा सहित सभी दल अपने कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों को "संस्कार" और "मर्यादित भाषा" का पाठ पढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन जब व्यवहारिक स्तर पर इन मूल्यों का पालन नहीं होता, तो इन अभियानों की सार्थकता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। (शेष पेज 2 पर)

विष्णुदेव साय सरकार के ढाई वर्ष

जनविश्वास को मजबूत करने की दिशा में बढ़ता छत्तीसगढ़

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में जिस प्रकार जनकल्याण, सुशासन और विकास को केंद्र में रखकर कार्य किया है, उसका प्रभाव अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। सरकार ने केवल घोषणाओं तक स्वयं को सीमित नहीं रखा, बल्कि योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने का प्रयास किया। यही कारण है कि आज प्रदेश में विकास और प्रशासनिक सक्रियता का नया वातावरण निर्मित हुआ है। विष्णुदेव साय सरकार ने सत्ता संभालते ही यह स्पष्ट कर दिया था कि शासन का केंद्र बिंदु आम नागरिक होगा। ग्रामीण विकास, किसानों का हित, महिलाओं का सशक्तिकरण,

युवाओं को रोजगार, बुनियादी सुविधाओं का विस्तार और पारदर्शी प्रशासन इन सभी क्षेत्रों में सरकार ने तेजी से कार्य किया। आज इन प्रयासों का परिणाम गांव से लेकर शहर तक महसूस किया जा रहा है।

किसानों को प्राथमिकता देने वाली सरकार

छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। यही कारण है कि विष्णुदेव साय सरकार ने किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। सरकार ने धान खरीदी व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित बनाने के साथ किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। समर्थन मूल्य और बोनस जैसी व्यवस्थाओं ने किसानों में विश्वास का वातावरण बनाया। सरकार ने सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने और फसल विविधीकरण पर भी जोर दिया। इससे किसान केवल पारंपरिक खेती तक सीमित न रहकर नई संभावनाओं की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। (शेष पेज 2 पर)

मध्यप्रदेश भाजपा में नई कार्य संस्कृति का उदाहरण है मजबूत संगठन, सशक्त संवाद

-विजया पाठक

मध्यप्रदेश में हाल के दिनों में हुई राजनीतिक नियुक्तियों ने संगठनात्मक प्रबंधन, आंतरिक समन्वय और रणनीतिक नेतृत्व को लेकर एक दिलचस्प उदाहरण प्रस्तुत किया है। इन घटनाक्रमों के केंद्र में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, संगठन मंत्री अजय जामवाल और मीडिया प्रमुख आशीष अग्रवाल की भूमिकाएँ चर्चा में रही हैं। इन तीनों के कार्यशैली और समन्वय को समझना प्रदेश की राजनीति के वर्तमान स्वरूप को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभालने के बाद हेमंत खंडेलवाल ने जिस तरह संगठन के भीतर संतुलन बनाने की कोशिश की, वह एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में देखा जा रहा है। किसी भी राजनीतिक दल में नियुक्तियों के दौरान असंतोष, गुटबाजी या विरोध की स्थिति बनना सामान्य माना जाता है, लेकिन हालिया नियुक्तियों में अपेक्षाकृत शांत वातावरण

बना रहना इस बात का संकेत देता है कि निर्णय प्रक्रिया में संवाद और संतुलन को प्राथमिकता दी गई। हालांकि, यह भी ध्यान देने योग्य है कि "कोई विरोध नहीं हुआ" जैसी धारणा का मूल्यांकन व्यापक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए, क्योंकि कई बार असहमति सतह पर दिखाई नहीं देती, बल्कि संगठनात्मक स्तर पर सीमित रह जाती है। (शेष पेज 3 पर)

सुशासन के दावों पर सवाल, लोधी विवाद ने उजागर किया भाजपा नेताओं का दोहरा चरित्र

(पेज 1 का शेष)

क्या यह माना जाए कि ये सारे प्रशिक्षण केवल औपचारिकता बनकर रह गए हैं? इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी स्पष्ट किया है कि सत्ता के करीब पहुंचते ही कई लोगों में जवाबदेही की भावना कमजोर पड़ जाती है। जनप्रतिनिधियों के परिजन स्वयं को कानून से ऊपर समझने लगते हैं, जो लोकतंत्र के लिए बेहद घातक प्रवृत्ति है। यदि समय रहते इस पर कठोर अंकुश नहीं लगाया गया, तो यह प्रवृत्ति समाज में अराजकता को जन्म दे सकती है।

छोटी मानसिकता के हैं विधायक प्रीतम लोधी

गरीब और आम जनता के साथ दुर्व्यवहार की खबरें सबसे अधिक पीड़ादायक होती हैं। लोकतंत्र का मूल उद्देश्य ही यही है कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को न्याय और सम्मान मिले। लेकिन जब वही व्यक्ति सत्ता के दंभ का शिकार होता है, तो यह पूरे तंत्र की विफलता को दर्शाता है। "सड़क पर कुचलने" जैसे आरोप केवल एक घटना नहीं, बल्कि उस मानसिकता का प्रतीक हैं, जिसमें आम नागरिक की जान और सम्मान का कोई मूल्य नहीं रह जाता। भाजपा के लिए यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह लंबे समय से "डबल इंजन सरकार" और सुशासन के मॉडल को अपनी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करती रही है। ऐसे में यदि उसके ही जनप्रतिनिधियों पर इस तरह के आरोप लगते हैं, तो विपक्ष को सरकार पर हमला करने का अवसर मिल जाता है और जनता के बीच विश्वास की कमी पैदा होती है।

पार्टी की कार्यवाही पर सबकी नजरें

यह समय केवल औपचारिक कार्रवाई का नहीं, बल्कि आत्ममंथन का है। क्या पार्टी अपने नेताओं और उनके परिवारों के लिए आचार संहिता को सख्ती से लागू कर पाएगी? क्या दोषियों के खिलाफ उदाहरण प्रस्तुत करने वाली कार्रवाई होगी? या फिर यह मामला भी समय के साथ ठंडे बस्ते में चला जाएगा? राजनीति में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए केवल विपक्ष का दबाव ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि सत्तारूढ़ दल को स्वयं आगे बढ़कर अनुशासन स्थापित करना होता है। यदि भाजपा इस मामले में पारदर्शी और कठोर रुख अपनाती है, तो यह उसके "सुशासन" के दावे को मजबूती देगा। लेकिन यदि कार्रवाई केवल दिखावे तक सीमित रही, तो यह संदेश जाएगा कि पार्टी अपने ही नेताओं के मामले में नरमी बरतती है।

लोकतंत्र में जनता की सुरक्षा खतरे में

यह स्पष्ट है कि जनप्रतिनिधियों का आचरण ही लोकतंत्र की विश्वसनीयता तय करता है। सत्ता का वास्तविक अर्थ सेवा है, न कि दबदबा। यदि इस मूल भावना को भुला दिया गया, तो लोकतंत्र केवल एक औपचारिक व्यवस्था बनकर रह जाएगा। इस प्रकरण ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि जनता सब देख रही है और समय आने पर उसका फैसला सबसे निर्णायक होता है। इसलिए यह जरूरी है कि राजनीतिक दल अपने भीतर अनुशासन और जवाबदेही की संस्कृति को मजबूत करें, ताकि जनता जनार्दन का विश्वास कायम रह सके।

नगरी निकायों और पंचायतों के चुनाव व उपचुनाव 01 जून को

-शशि पांडे

जगत प्रवाह, रायपुर। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरी निकायों और पंचायतों के चुनाव व उपचुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया। दोनों चुनाव एक ही चरण में संपन्न होंगे। आयोग के अनुसार एक जून को मतदान कराया जाएगा, जबकि चार जून को परिणाम घोषित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 11 मई से शुरू होगी और 18 मई तक चलेगी। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 19 मई को की जाएगी। उम्मीदवार 21 मई तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। नगरी निकायों में अध्यक्ष के पांच और पार्षदों के 77 रिक्त पदों पर मतदान होगा। वहीं पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य के 10, सरपंच के 82 और पंच के 1136 रिक्त पदों के लिए चुनाव कराया जाएगा। नगरी निकायों के 44,525 तथा पंचायतों के 10,37,789 मतदाता चुनाव में भाग लेंगे। मतदान के लिए नगरी निकायों में 115 और पंचायतों में 937 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आयोग की सचिव शिखा राजपूत तिवारी ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए 33 सामान्य प्रेक्षक नियुक्त किए गए हैं।

ईवीएम और बैलेट से मतदान

नगरी निकायों में मतदान ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) से कराया जाएगा, जबकि पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। नगरी निकायों में मतदान सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक और पंचायतों में सुबह सात बजे से दोपहर तीन बजे तक होगा।

जनविश्वास को मजबूत करने की दिशा में बढ़ता छत्तीसगढ़

(पेज 1 का शेष)

महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में प्रभावी कदम

विष्णुदेव साय सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई योजनाओं को गति दी। महिला स्व-सहायता समूहों को आर्थिक सहायता, स्वरोजगार के अवसर और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया गया। सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचने लगा है। आज अनेक महिलाएं लघु उद्योग, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य स्वरोजगार गतिविधियों से जुड़कर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं। महिलाओं की सामाजिक भागीदारी बढ़ना भी सरकार की सकारात्मक उपलब्धियों में गिना जा रहा है।

युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास

किसी भी राज्य के विकास में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। विष्णुदेव साय सरकार ने युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कई योजनाएं प्रारंभ कीं। कौशल विकास प्रशिक्षण, औद्योगिक निवेश और स्थानीय रोजगार सृजन की दिशा में गंभीर प्रयास किए गए। राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक नीति लागू की गई। इसका उद्देश्य केवल उद्योग स्थापित करना नहीं, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार करना है। सरकार ने तकनीकी शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को भी रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया है।

आदिवासी क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान

छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल राज्य है और विष्णुदेव साय स्वयं आदिवासी समाज से आते हैं। यही कारण है कि सरकार ने आदिवासी अंचलों के विकास को विशेष प्राथमिकता दी। सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए कई योजनाएं तेजी से लागू की गईं। वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रशासनिक सक्रियता बढ़ाई गई। वन उपज संग्रहण और उसके उचित मूल्य की व्यवस्था ने आदिवासी समुदाय की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायता की है।

बुनियादी ढांचे के विकास को मिली गति

विकास की वास्तविक पहचान मजबूत आधारभूत संरचना से होती है। विष्णुदेव साय सरकार ने सड़क, पुल, बिजली और शहरी विकास कार्यों को प्राथमिकता दी। राज्य में कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को गति मिली, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संपर्क बेहतर हुआ। नई पेयजल योजनाएं, ग्रामीण विद्युतीकरण और नगरीय विकास परियोजनाएं भी तेजी से

आगे बढ़ रही हैं। इससे लोगों के दैनिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगा है।

डिजिटल गवर्नेंस और प्रशासनिक पारदर्शिता

सरकार ने प्रशासन को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में डिजिटल तकनीक का उपयोग बढ़ाया। ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार, डिजिटल भुगतान और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने से आम नागरिकों को राहत मिली है। सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे हितग्राहियों तक पहुंचे, इसके लिए तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था विकसित की गई। इससे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और योजनाओं की पारदर्शिता में सुधार हुआ है।

स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार

विष्णुदेव साय सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, अस्पतालों के उन्नयन और चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों की आधारभूत सुविधाओं में सुधार, डिजिटल शिक्षा और विद्यार्थियों के लिए नई योजनाओं का लाभ दिखाई देने लगा है। सरकार का प्रयास है कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो।

कानून व्यवस्था और सुशासन पर फोकस

किसी भी राज्य के विकास के लिए कानून व्यवस्था मजबूत होना आवश्यक है। विष्णुदेव साय सरकार ने प्रशासनिक सख्ती और सुशासन के माध्यम से जनता में विश्वास बढ़ाने का प्रयास किया। भ्रष्टाचार और अव्यवस्थाओं पर नियंत्रण को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट दिखाई दिया है। सरकार ने यह संदेश देने का प्रयास किया कि शासन केवल सत्ता संचालन का माध्यम नहीं, बल्कि जनता की समस्याओं के समाधान का दायित्व है।

निवेश और औद्योगिक विकास की नई संभावनाएं

छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है। सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने और निवेश आकर्षित करने के लिए नई नीतियों को लागू किया। इससे राज्य में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने लगी है। आईटी, ऊर्जा, खनिज और कृषि आधारित उद्योगों के क्षेत्र में नए निवेश प्रस्ताव सामने आए हैं। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की संभावना बढ़ी है।

जनसंवाद से मजबूत हुआ विश्वास

विष्णुदेव साय की कार्यशैली की सबसे बड़ी विशेषता उनका सरल और जनसंपर्क आधारित नेतृत्व माना जा रहा है। वे लगातार जनता, कार्यकर्ताओं और विभिन्न वर्गों से संवाद बनाए हुए हैं। इससे सरकार और जनता के बीच विश्वास का वातावरण मजबूत हुआ है। जनसमस्याओं को सीधे सुनने और उनके समाधान की दिशा में कार्य करने की शैली ने उन्हें जनप्रिय नेतृत्व के रूप में स्थापित किया है।

विकास और जनकल्याण की नई दिशा

ढाई वर्षों के कार्यकाल में विष्णुदेव साय सरकार ने यह साबित करने का प्रयास किया है कि यदि शासन की प्राथमिकता जनता हो, तो विकास का प्रभाव धरातल पर दिखाई देने लगता है। किसानों, महिलाओं, युवाओं, आदिवासियों और गरीब वर्ग के हितों को केंद्र में रखकर लिए गए फैसलों का सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगा है। छत्तीसगढ़ में विकास, निवेश, सुशासन और जनकल्याण को लेकर एक नई उम्मीद दिखाई देती है। आने वाले वर्षों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इन योजनाओं और नीतियों को किस गति से आगे बढ़ाती है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि विष्णुदेव साय सरकार ने अपने ढाई वर्षों में जनविश्वास अर्जित करने की दिशा में मजबूत आधार तैयार कर लिया है।

मध्यप्रदेश भाजपा में नई कार्य संस्कृति का उदाहरण है मजबूत संगठन, सशक्त संवाद

(पेज 1 का शेष)

खंडेलवाल के साथ जामवाल का समन्वय सटीक

अजय जामवाल, जो संगठनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनके साथ खंडेलवाल का समन्वय भी इस प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है। संगठन मंत्री की भूमिका परंपरागत रूप से पार्टी के ढांचे को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं के बीच संवाद बनाए रखने और रणनीतिक फैसलों को जमीन पर लागू करने से जुड़ी होती है। ऐसे में यदि प्रदेश नेतृत्व और संगठन के बीच तालमेल प्रभावी रहता है, तो उसका असर नियुक्तियों और संगठनात्मक स्थिरता पर पड़ता है। इस संदर्भ में दोनों नेताओं की संयुक्त कार्यशैली को एक "समन्वय मॉडल" के रूप में देखा जा सकता है, हालांकि इसकी दीर्घकालिक सफलता का आंकलन भविष्य की राजनीतिक परिस्थितियों में ही स्पष्ट होगा। पार्टी के भीतर संभावित खींचतान को समय रहते सुलझाना भी किसी नेतृत्व की बड़ी परीक्षा होती है। उपलब्ध संकेतों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मतभेदों को खुलकर टकराव में बदलने से पहले ही नियंत्रित करने की कोशिश की गई। यह रणनीति अल्पकाल में स्थिरता तो देती है, लेकिन इसके साथ यह भी जरूरी है कि विभिन्न स्तरों पर संवाद की प्रक्रिया निरंतर बनी रहे, ताकि दबे हुए असंतोष भविष्य में उभरकर बड़ी चुनौती न बनें।

आशीष अग्रवाल ने मीडिया प्रबंधन में पेश की नजीर

भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रबंधन की दृष्टि से आशीष अग्रवाल की भूमिका भी उल्लेखनीय बताई जा रही है। मीडिया प्रभारी के रूप में उनकी जिम्मेदारी केवल खबरों का संप्रेषण नहीं, बल्कि पार्टी की छवि को आकार देने की भी होती है। हाल के समय में जिस तरह मीडिया समन्वय और संदेशों की एकरूपता बनाए रखने की कोशिश हुई है, उसे एक संगठित रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है। हालांकि, "सबसे उत्तम उदाहरण" जैसे दावों का आंकलन तुलनात्मक और दीर्घकालिक प्रदर्शन के आधार पर ही अधिक संतुलित तरीके से किया जा सकता है। मीडिया प्रबंधन के क्षेत्र में यह भी महत्वपूर्ण है कि पार्टी का दृष्टिकोण केवल प्रचार तक सीमित न रहकर संवादात्मक हो- जहाँ विभिन्न मुद्दों पर प्रतिक्रिया, स्पष्टीकरण और जनसरोकारों से जुड़ाव भी शामिल हो।

पार्टी के लिए यह सकारात्मक संकेत

कुल मिलाकर मध्यप्रदेश में हालिया राजनीतिक नियुक्तियाँ और उनसे जुड़ी प्रक्रियाएँ यह संकेत देती हैं कि संगठनात्मक संतुलन, नेतृत्व के बीच समन्वय और मीडिया प्रबंधन ये तीनों पहलू किसी भी राजनीतिक दल की कार्यक्षमता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हेमंत खंडेलवाल, अजय जामवाल और आशीष अग्रवाल की भूमिकाओं को इसी व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझना अधिक उपयुक्त होगा। हालांकि, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की वास्तविक परीक्षा समय के साथ होती है जब निर्णयों के परिणाम सामने आते हैं, कार्यकर्ताओं की संतुष्टि का स्तर स्पष्ट होता है और जनता के बीच छवि का वास्तविक आकलन होता है। इसलिए वर्तमान परिदृश्य को एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा सकता है।

जाति, क्षेत्र और नेतृत्व का बेहतर संतुलन

मध्यप्रदेश भाजपा में हाल ही में की गई नियुक्तियों ने यह दिखाया कि पार्टी में संतुलित नेतृत्व की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। यह नियुक्तियाँ ना केवल पार्टी के भीतर समरसता और संतुलन की मिसाल प्रस्तुत करती हैं, बल्कि इसने यह भी साबित किया है कि भाजपा जाति, क्षेत्र और नेतृत्व के स्तर पर संतुलन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इन नियुक्तियों में विभिन्न वर्गों, समाज के हर हिस्से और पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को समान प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। इससे न केवल भाजपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है, बल्कि पार्टी के भीतर नेतृत्व की नयी दिशा भी दिखाई दे रही है। इसके अलावा, मध्यप्रदेश में भाजपा की नियुक्तियाँ नेतृत्व के विभिन्न स्तरों पर युवा और अनुभवी नेताओं के बीच सामंजस्य बनाने का भी प्रयास हैं। यह निर्णय पार्टी को न सिर्फ राज्य में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी मजबूती प्रदान कर सकते हैं।

नियुक्तियों से भाजपा के भविष्य में सकारात्मक बदलाव की संभावना

इन नियुक्तियों के जरिए भाजपा ने यह दिखाया है कि वह युवा नेतृत्व, अनुभवी नेताओं और विभिन्न सामाजिक वर्गों को एक साथ लेकर चलने की दिशा में काम कर रही है। ऐसे में पार्टी को न केवल अपने पारंपरिक वोट बैंक को बनाए रखने में मदद मिल सकती है, बल्कि नए और युवा मतदाताओं को भी आकर्षित करने का एक अच्छा अवसर मिल सकता है। यह कदम भाजपा को राज्य स्तर पर भी मजबूती दे सकता है, क्योंकि संतुलित नेतृत्व के जरिए विभिन्न समूहों के बीच विश्वास और समर्पण बढ़ता है। इसके अलावा, यदि यह संतुलन पार्टी के भीतर सुलह और सामंजस्य को बढ़ाता है, तो भाजपा को संगठनात्मक रूप से भी लाभ हो सकता है, जिससे आगामी चुनावों में उसकी स्थिति मजबूत होगी।

योगी और धामी ने किया संयुक्त रूप से कई विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास

-प्रमोद कुमार

जगत प्रवाह. देहरादून। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संयुक्त रूप से यमकेश्वर क्षेत्र का भ्रमण कर महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय बिथ्याणी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गाँव पंचूर पहुँचे। यहाँ उन्होंने श्री विष्णु महायज्ञ में प्रतिभाग किया और परिवार व ग्रामीणों के साथ आध्यात्मिक अनुष्ठान का हिस्सा बने। मुख्यमंत्री योगी ने मंदिर समिति का आभार जताते हुए कहा कि तीन वर्ष पूर्व जहाँ केवल श्रद्धा का भाव था, आज वहाँ भव्य मंदिर खड़ा है। युवाओं को प्रेरित करते हुए उन्होंने कहा जीवन में प्रगति के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण का होना अनिवार्य है। अच्छा सोचने से परिणाम सुखद होते हैं, और इस सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए ईश्वर की भक्ति और आध्यात्मिकता ही सबसे सशक्त माध्यम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व की सराहना करते हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' की बरसी का उल्लेख किया। उन्होंने क्षेत्र को बड़ी सौगात देते हुए बिथ्याणी महाविद्यालय को 'आदर्श कॉलेज' के रूप में विकसित करने और क्षेत्र में मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को वैश्विक स्तर की शिक्षा और खेल सुविधाएं देने हेतु संकल्पबद्ध है, जिसके क्रम में इस महाविद्यालय को हाईटेक किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल की जीत संगठन और नेतृत्व की विश्वसनीयता का परिणाम: राकेश सिंह

-नरेन्द्र दीक्षित

जगत प्रवाह. नर्मदापुरम। चुनाव में आए परिणाम अद्भुत हैं और हमें अपने नेतृत्व पर गर्व है, जिनकी लोकप्रियता, जनता में विश्वसनीयता और सशक्त रणनीति के कारण पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत के साथ सरकार बनाई। उक्त विचार मध्यप्रदेश शासन के मंत्री एवं नर्मदापुरम जिला प्रभारी राकेश सिंह ने भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित जिला बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। बैठक को संबोधित करते हुए संभाग प्रभारी कांतदेव सिंह ने कहा कि संगठन के निर्देशानुसार मंडल से लेकर संभाग स्तर तक तथा शक्ति केंद्र से लेकर बूथ स्तर तक की बैठकें निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करना आवश्यक है। जिला प्रभारी अलकेश आर्य ने कहा कि 16 एवं 17 मई को आयोजित होने वाले प्रशिक्षण वर्ग की तैयारियों को लेकर गंभीरता से कार्य करना होगा। इसके लिए प्रशिक्षण वर्ग की जिला टोली का गठन कर दायित्वों का विभाजन किया जाएगा। जिला अध्यक्ष प्रीति शुक्ला ने बैठक की प्रस्तावना रखते हुए संगठन द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों एवं जिला प्रशिक्षण अभियान की जानकारी दी।

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बीच रोजगार बचाने की मांग तेज

-बद्रीप्रसाद कौरव

जगत प्रवाह. गाडरवारा। शहर में चल रही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर अब छोटे व्यापारियों और रोजगार से जुड़े लोगों की चिंता भी सामने आने लगी है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान किसी भी गरीब एवं मेहनतकश व्यक्ति का रोजगार प्रभावित न हो। मांग है कि शहर में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो ठेला, गुमटी, चाय-पान, फल-सब्जी और छोटे व्यवसायों के माध्यम से अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं। यदि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के कार्रवाई की जाती है तो अनेक परिवार बेरोजगारी और आर्थिक संकट का सामना करेंगे। प्रशासन से मांग है कि जिन लोगों का अतिक्रमण के दौरान रोजगार प्रभावित हो रहा है, उनकी लिस्टिंग कर कर स्थानीय औद्योगिक इकाइयों में एवं उनके लिए शासकीय नजूल भूमि पर स्थायी हॉकर जोन विकसित किए जाएं तथा व्यवस्थित दुकानें बनाकर किराये या निर्धारित व्यवस्था के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही पूर्व में बने लेकिन बंद पड़े हॉकर जोन का लाभ भी वास्तविक जरूरतमंदों को दिए जाने की मांग की गई है। यह भी कहा गया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पारदर्शिता और समानता के साथ हो तथा किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट एवं प्रशासनिक आदेशों के अनुसार पूर्व सूचना देकर मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए कार्रवाई की जाए।

सम्पादकीय

बंगाल चुनाव: भाजपा की जीत प्रत्याशित या अप्रत्याशित

पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से देश की सबसे जटिल और बहुआयामी राजनीतिक प्रयोगशालाओं में गिनी जाती रही है। यहां सत्ता परिवर्तन केवल चुनावी आंकड़ों का विषय नहीं होता, बल्कि यह वैचारिक संघर्ष, सामाजिक मनोविज्ञान और जनभावनाओं की दिशा तय करने वाला राजनीतिक संकेत भी माना जाता है। ऐसे में बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सफलता को लेकर यह प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या यह जीत पहले से तय दिखाई दे रही थी या फिर यह पूरी तरह अप्रत्याशित राजनीतिक परिणाम है। यदि पिछले एक दशक की राजनीतिक परिस्थितियों को देखा जाए, तो भाजपा का बंगाल में उभार अचानक नहीं कहा जा सकता। पार्टी ने धीरे-धीरे अपने संगठन को मजबूत किया, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं का नेटवर्क खड़ा किया और राज्य की राजनीति में खुद को मुख्य विपक्ष के रूप में स्थापित किया। लंबे समय तक बंगाल में वामपंथ और बाद में तृणमूल कांग्रेस का प्रभाव रहा, लेकिन भाजपा ने लगातार वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनने की दिशा में काम किया। इस दृष्टि से देखें तो भाजपा की जीत पूरी तरह अप्रत्याशित नहीं कही जा सकती।

हालांकि यह भी सत्य है कि बंगाल जैसे राज्य में भाजपा को सत्ता के करीब पहुंचाने वाली परिस्थितियां अपने आप निर्मित नहीं हुईं। इसके पीछे राज्य की बदलती राजनीतिक परिस्थितियां और जनता के भीतर बढ़ती असंतुष्टि भी प्रमुख कारण रही। वर्षों तक एक ही राजनीतिक संस्कृति में रहने के बाद आम मतदाता बदलाव चाहता था। बेरोजगारी, राजनीतिक हिंसा, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक पक्षपात जैसे मुद्दों ने जनता के भीतर असंतोष को जन्म दिया। भाजपा ने इसी असंतोष को राजनीतिक समर्थन में बदलने का प्रयास किया। भाजपा की रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि उसने बंगाल की राजनीति को केवल चुनावी अभियान तक सीमित नहीं रखा। पार्टी ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, बंगाल की अस्मिता और स्थानीय नेतृत्व को साथ लेकर जनाधार बढ़ाने का प्रयास किया। यही कारण है कि भाजपा गांवों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक अपनी पकड़ मजबूत करने में सफल होती दिखाई दी।

इस चुनाव में भाजपा के पक्ष में सबसे बड़ी बात उसका संगठनात्मक विस्तार रहा। पार्टी ने बूथ प्रबंधन, सोशल मीडिया, जनसभाओं और स्थानीय मुद्दों पर निरंतर सक्रियता बनाए रखी। राष्ट्रीय नेतृत्व की लगातार मौजूदगी और राज्य स्तर पर आक्रामक रणनीति ने भी चुनाव को भाजपा के पक्ष में मोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।इसके साथ ही यह भी स्वीकार करना होगा कि बंगाल चुनाव में भाजपा की सफलता केवल उसके संगठन की उपलब्धि नहीं थी, बल्कि विपक्ष की कमजोरियों का भी परिणाम रही। जब किसी राज्य में लंबे समय तक एक ही दल सत्ता में रहता है, तो सत्ता विरोधी भावना स्वाभाविक रूप से विकसित होने लगती है। बंगाल में भी यही स्थिति दिखाई दी। जनता के एक बड़े वर्ग ने बदलाव की संभावना के रूप में भाजपा को देखा। फिर भी इस जीत को पूरी तरह आसान या पूर्व निर्धारित नहीं कहा जा सकता। बंगाल की सामाजिक और राजनीतिक संरचना हमेशा से अलग रही है। यहां बाहरी राजनीतिक प्रभावों को तुरंत स्वीकार नहीं किया जाता। भाजपा को यहां अपनी विचारधारा और नेतृत्व को स्वीकार्य बनाने के लिए लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। कई बार राजनीतिक हिंसा और कार्यकर्ताओं पर हमलों जैसी परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ा। ऐसे में भाजपा का लगातार मजबूत होना उसकी राजनीतिक धैर्य क्षमता को दर्शाता है। इस चुनाव का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी रहा कि भाजपा ने पहली बार बंगाल की राजनीति में खुद को केवल विपक्ष नहीं, बल्कि सत्ता के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया। यही बदलाव चुनाव परिणामों में दिखाई दिया। जनता ने भाजपा को गंभीरता से लेना शुरू किया और यह स्थिति पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है।

अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या यह जीत स्थायी राजनीतिक परिवर्तन का संकेत है या केवल परिस्थितिजन्य परिणाम। इसका उत्तर आने वाले वर्षों की राजनीति तय करेगी। भाजपा के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती जनता के विश्वास को बनाए रखने और बंगाल की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की होगी। केवल चुनाव जीतना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि जनता के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना ही किसी राजनीतिक दल की वास्तविक परीक्षा होती है। बंगाल चुनाव में भाजपा की जीत न पूरी तरह अप्रत्याशित थी और न ही पूरी तरह निश्चित। यह लंबे राजनीतिक संघर्ष, संगठनात्मक विस्तार, जनता की बदलती मन:स्थिति और सत्ता विरोधी लहर का संयुक्त परिणाम थी। भाजपा ने बंगाल में जिस प्रकार अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की, उसने यह सिद्ध कर दिया कि लोकतंत्र में निरंतर प्रयास और मजबूत रणनीति किसी भी राजनीतिक समीकरण को बदल सकती है।

सियासी गहमागहमी

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चर्चा के केंद्र में हैं। हाल के घटनाक्रमों और विभिन्न मामलों में बढ़ती जांच गतिविधियों ने राजनीतिक गलियारों में यह संकेत देना शुरू कर दिया है कि आने वाले समय में उनकी राजनीतिक और कानूनी चुनौतियां बढ़ सकती हैं। विपक्ष लगातार कांग्रेस शासनकाल के दौरान लिए गए निर्णयों और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है, वहीं जांच एजेंसियों की सक्रियता ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। भूपेश बघेल लंबे समय तक छत्तीसगढ़ कांग्रेस का मजबूत चेहरा रहे हैं और किसान, ग्रामीण तथा सामाजिक मुद्दों के कारण उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई थी। हालांकि सत्ता परिवर्तन के बाद प्रदेश की राजनीति का स्वरूप तेजी से बदला है। भाजपा अब कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की कई योजनाओं, निर्णयों और कथित अनियमितताओं को लेकर आक्रामक रुख अपनाए हुए है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि जांच एजेंसियों की कार्रवाई तेज होती है, तो इसका असर केवल व्यक्तिगत छवि तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रदेश कांग्रेस की राजनीतिक रणनीति पर भी पड़ सकता है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि भूपेश बघेल इन चुनौतियों का सामना किस राजनीतिक और कानूनी रणनीति के साथ करते हैं।

मप्र कांग्रेस में शीर्ष स्तर पर बदलाव की सुगबुगाहट तेज

कांग्रेस की मध्यप्रदेश इकाई में एक बार फिर संगठनात्मक बदलाव की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में तेज होती दिखाई दे रही हैं। लगातार चुनावी चुनौतियों, संगठनात्मक निष्क्रियता और जमीनी स्तर पर कमजोर पड़ती पकड़ के बीच अब पार्टी के भीतर शीर्ष नेतृत्व में परिवर्तन को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच यह भावना उभर रही है कि आगामी चुनावी रणनीति को प्रभावी बनाने के लिए संगठन में नई ऊर्जा और नए नेतृत्व की आवश्यकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधानसभा और लोकसभा चुनावों के बाद पार्टी के भीतर आत्ममंथन की प्रक्रिया लगातार चल रही है। संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने, कार्यकर्ताओं में विश्वास बढ़ाने और जनता के बीच मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए नेतृत्व परिवर्तन को एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सार्वजनिक रूप से किसी बड़े बदलाव की संभावना से इनकार करते नजर आते हैं, लेकिन अंदरूनी बैठकों और बढ़ती राजनीतिक सक्रियता ने संकेत देना शुरू कर दिया है कि आने वाले समय में संगठनात्मक फेरबदल हो सकता है। यदि ऐसा होता है, तो इसका सीधा असर प्रदेश की राजनीतिक दिशा और कांग्रेस की भविष्य की रणनीति पर दिखाई दे सकता है।

हफ्ते का कार्टून

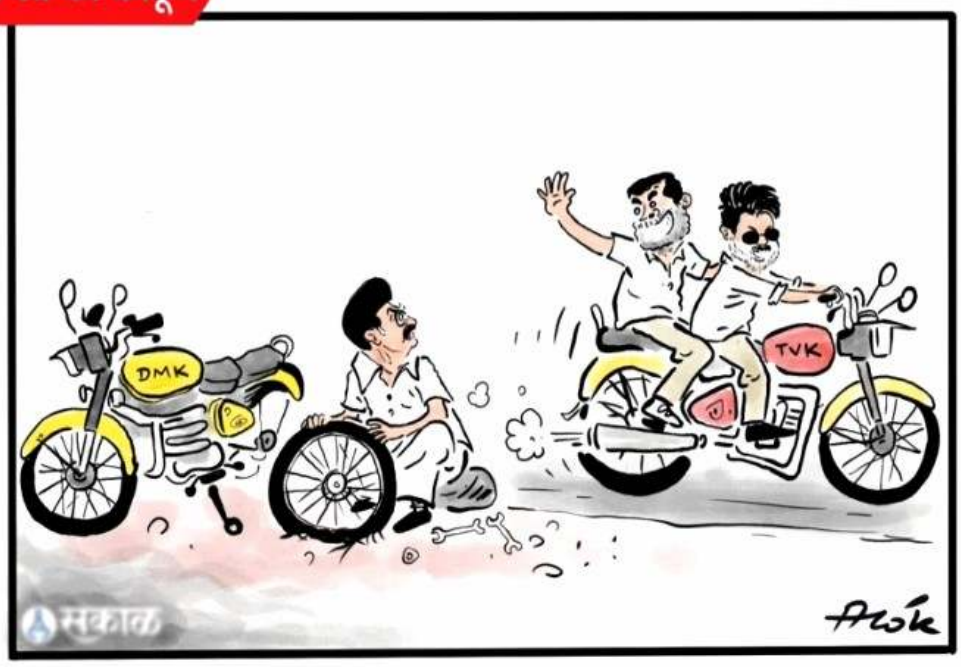

ट्वीट-ट्वीट

मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे - सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो।

ये उपदेश नहीं - ये नाकामी के सबूत हैं।

-राहुल गांधी

कांग्रेस नेता @RahulGandhi

मध्य प्रदेश की जनता को अब यह दिन देखने पड़ रहे हैं कि किसानों के हक की लड़ाई लड़ने पर उज्जैन के जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक जाट जी को जिला बदर कर दिया जाता है।

और जब इसका विरोध करने के लिए कांग्रेस विधायक महेश परमार और अन्य नेता कलेक्टर से मिलने जाना चाहते हैं तो उन्हें शहर से बाहर रोक दिया जाता है।

-कमलनाथ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

राष्ट्रीय स्तर के प्रभावशाली नेताओं की श्रेणी में स्थापित हैं शुभेंदु अधिकारी

समता पाठक/जगत प्रवाह

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भारतीय राजनीति के उन नेताओं में गिने जाते हैं, जिन्होंने जमीनी संघर्ष, संगठन क्षमता और जनसंपर्क के बल पर अपनी अलग पहचान बनाई है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में उनका नाम एक प्रभावशाली और आक्रामक नेता के रूप में लिया जाता है। वे वर्तमान में पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और राज्य में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख चेहरों में शामिल हैं। शुभेंदु अधिकारी का जन्म 15 दिसंबर 1970 को पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के कांथी क्षेत्र में हुआ। उनका परिवार लंबे समय से राजनीति और सामाजिक जीवन से जुड़ा रहा है। उनके पिता शिशिर अधिकारी भी वरिष्ठ राजनेता रहे हैं और कई बार सांसद चुने गए। राजनीतिक वातावरण में पले-बढ़े शुभेंदु अधिकारी ने प्रारंभ से ही जनसेवा और सामाजिक गतिविधियों में रुचि दिखाई। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पश्चिम बंगाल में ही प्राप्त की और बाद में राजनीति विज्ञान विषय में स्नातक की पढ़ाई पूरी की।

राजनीतिक जीवन की शुरुआत उन्होंने छात्र राजनीति से की। शुरुआती दौर में वे युवा कांग्रेस और बाद में तृणमूल कांग्रेस से जुड़े। पश्चिम बंगाल की राजनीति में उनका कद उस समय तेजी से बढ़ा जब उन्होंने नंदीग्राम आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2007 में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ हुए इस आंदोलन ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया था। शुभेंदु अधिकारी उस आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल रहे और ग्रामीण जनता के बीच मजबूत जनाधार बनाने में सफल हुए। नंदीग्राम आंदोलन के बाद वे राज्य राजनीति में एक बड़े जननेता के रूप में स्थापित हो गए। तृणमूल कांग्रेस के साथ रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालीं। वे सांसद भी रहे और बाद में पश्चिम बंगाल सरकार में परिवहन, सिंचाई और जल संसाधन जैसे विभागों के मंत्री बने। संगठन और प्रशासन दोनों क्षेत्रों में उनकी कार्यशैली को प्रभावी माना जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी पकड़ और जनता से सीधे संवाद की शैली ने उन्हें राज्य के प्रभावशाली नेताओं में शामिल कर दिया। हालांकि समय के साथ तृणमूल कांग्रेस और शुभेंदु अधिकारी के बीच मतभेद बढ़ने लगे। वर्ष 2020 में उन्होंने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। उनका भाजपा में शामिल होना पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम माना गया। भाजपा ने उन्हें राज्य में मजबूत संगठनात्मक नेतृत्व के रूप में आगे बढ़ाया।

वर्ष 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ा। इस चुनाव की सबसे बड़ी चर्चा इस बात को लेकर रही कि उनका मुकाबला तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी से था। बेहद कड़े मुकाबले में शुभेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की। इस जीत ने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में भी चर्चित चेहरा बना दिया। इसके बाद उन्हें पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। शुभेंदु अधिकारी को भाजपा के आक्रामक और रणनीतिक नेताओं में गिना जाता है। वे अक्सर राज्य सरकार की नीतियों और प्रशासनिक निर्णयों को लेकर मुखर रहते हैं। बंगाल में भाजपा संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में उत्साह बनाए रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। वे लगातार जनसभाओं, आंदोलनों और संगठनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच सक्रिय रहते हैं। उनकी राजनीतिक शैली सीधी और स्पष्ट मानी जाती है। समर्थकों के बीच उनकी छवि एक संघर्षशील नेता की है, जबकि विरोधी उन्हें भाजपा की बंगाल राजनीति का सबसे प्रभावशाली चेहरा मानते हैं। ग्रामीण बंगाल में उनकी लोकप्रियता और संगठन पर पकड़ भाजपा के लिए बड़ी ताकत मानी जाती है। राजनीतिक जीवन के अलावा शुभेंदु अधिकारी सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहते हैं। वे बंगाल की सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक परंपराओं और स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाते रहे हैं। यही कारण है कि वे केवल एक राजनीतिक नेता नहीं, बल्कि जनभावनाओं से जुड़े जनप्रतिनिधि के रूप में भी पहचान रखते हैं। आज पश्चिम बंगाल की राजनीति में शुभेंदु अधिकारी भाजपा की सबसे मजबूत आवाजों में गिने जाते हैं। संघर्ष, संगठन और जनसंपर्क की राजनीति के जरिए उन्होंने स्वयं को राष्ट्रीय स्तर के प्रभावशाली नेताओं की श्रेणी में स्थापित किया है।

पड़ोसी देशों में राजनीतिक हलचल?

रघु ठाकुर
सामाजिक कार्यकर्ता, विचारक और समाजवादी नेता

भारत के दो पड़ोसी देशों के चुनाव हाल ही में संपन्न हुए। दोनों जगह अलग-अलग ढंग से जेन जी याने वह युवा पीढ़ी जो 1997 या उसके बाद की है, के द्वारा सरकारों के विरुद्ध विद्रोह हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप वहां की सरकारें भंग हुई तथा वहाँ नये चुनाव हुए। वैसे तो कुछ दिनों पूर्व श्रीलंका के भी चुनाव ऐसे ही जेन जी के आंदोलन के बाद हुए थे जिसमें काफी हिंसा और लूटपाट हुई थी और वहाँ की लंबे समय से निर्वाचित सरकार को हटना पड़ा और सेना ने नियंत्रण किया था। वहाँ एक नौजवान चुनकर आये व राष्ट्रपति बने तथा ऐसा कहा जाता है कि वे मार्क्सवादी है और चीन समर्थक है। हालांकि अभी तक उन्होंने चीनी विदेश नीति के लक्ष्यों को कम से कम जाहरातौर पर अमल में नहीं लाया है और न ही उसके वे खिलाफ भी है। याने विचारधारा चाहे जो भी हो परंतु वे अपने देश के हितों के अनुकूल शांत तरीके से निर्णय लेकर आगे बढ़ रहे हैं। श्रीलंका और भारत के बीच में उन्होंने चीनी लाइन को बाधा नहीं बनने दिया। यह उनकी समझदारी और विदेश नीति का संतुलन ही कहा जाना चाहिए। बंगलादेश में जो इस्लामिक युवा विद्रोह हुआ था। उस समय एक चिंता भारत व अन्य देशों में उत्पन्न हुई थी कि उसके बाद बंगलादेश कहीं फिर से सैनिक तानाशाही में तो नहीं फँस जायेगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री हसीना को सेना के संकेत पर देश छोड़कर भागना पड़ा और उन्होंने भारत में शरण ली। युनूस को विदेश से वापिस बुलाकर उनको देश का कार्यभार सौंपा गया, जिसे सेना ने भी स्वीकार किया था। यह आश्चर्यजनक भी था कि युनूस को अमेरिका समर्थक माना जाता है। उन्हें एक प्रकार सेना ने स्वीकार किया, बंगलादेश के लोगों ने स्वीकार किया, उससे इतना संकेत तो मिलता ही है कि बंगलादेश की उथल पुथल की डोर कहीं न कहीं अमेरिका के पास रही है। वहाँ, इस्लामिक छात्रों ने तत्कालीन शेख हसीना की सरकार व उनकी पार्टी के खिलाफ हिंसक विद्रोह शुरू किया था। प्रधानमंत्री से लेकर अनेकों मंत्रियों को भागना पड़ा था और सेना ने भी एक प्रकार से विद्रोही इस्लामिक कटटरपंथियों का साथ दिया था। उस समय तीन प्रकार की संभावनायें सामने आई थीं एक, युनूस अंतरिम कार्यकारी मुखिया थे ही उनको बंगलादेश का आगामी मुखिया बनाया जा सकता था। दूसरा, जिन कटटरपंथी युवाओं ने वहां विद्रोह शुरू किया था, तब मुझे लगता है कि यह विदेशी शक्तियों द्वारा प्रायोजित था। चुनावों के बाद उनकी सत्ता आयेगी, तीसरा अनुमान था कि सेना ही सत्ता अपने हाथ में ले लेगी। इन सब घटनाक्रम के पीछे चीन और अमेरिकन शक्तियों का अनुमार्तित संघर्ष लगता था। शेख हसीना चीन के दौरे से लौटकर आई थीं और सत्ता पलट का खेल शुरू हो गया था। याने चीन के साथ उनका जो अंतर संबंध था वह दुनिया के चीन विरोधी समूह को स्वीकार नहीं था। बंगलादेश में भी आश्चर्यजनक रूप से उसी प्रकार सेना ने भूमिका अदा की जिस प्रकार श्रीलंका में मिस्र में या एक जमाने में रूस में की थी। एक अर्थ में स्थिति साफ है कि बंगलादेश की सेना कहीं न कहीं भले ही अपने आर्थिक या अन्य हितों के चलते वैश्विक शक्तियों के इशारे पर काम कर रही थी।

जिस घटनाक्रम को लेकर बंगलादेश में छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ था, जो बाद में सारे बंगलादेश में फैला। बाद में यह कटटरपंथी इस्लामिक छात्रों व युवा नेतृत्व के पास चला गया था। इस आंदोलन की शुरूआत एक मामूली घटना से हुई थी। शेख हसीना की सरकार ने बंगलादेश की मुक्ति वाहिनी (जो उनके पिता व बंगलादेश के जनक शेख मुजीब के द्वारा बनाई गई थी) के उन परिवारजनों को जो बंगलादेश के निर्माण आंदोलन में जेलों में गये थे, यातनायें सही थी, पाकिस्तानी जुल्म सहे थे, को विभिन्न शासकीय पदों व नौतियों में आरक्षण में वृद्धि दी, जिसके खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था। यह बात भी सही है कि बंगलादेश के निर्माण व इस आंदोलन को आज लगभग 55 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और इस आंदोलन के हिस्सेदार लोग अब बहुत कम ही बचे है परंतु उनके परिजनों को मिल रही आरक्षण और वृद्धि के प्रस्ताव का विरोध इन नौजवानों द्वारा किया था। इसको लेकर पहले मुक्ति वाहिनी के समर्थक छात्रों और आरक्षण के विरोधी छात्रों के मध्य टकराव शुरू हुआ जो बढ़कर बंगलादेश में सत्ता परिवर्तन का कारण बना। कभी-कभी ऐसी कुछ घटनायें आश्चर्यजनक ढंग से होती हैं जहां पर छोटे से सवालों से शुरू हुए आंदोलन, कुछ ही दिनों में विशालकाय आंदोलन का रूप ले लेते है। 1974 में गुजरात में छात्रों का आंदोलन छात्रावास में मेस की थाली के दाम बढ़ाने से शुरू हुआ था जो बाद में गुजरात सरकार को भंग करने का कारण बना। फिर बिहार व देश के अनकों इलाकों में यह आंदोलन फैला, देश में आपातकाल लगा और देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सत्ता से हटना पड़ा।

युनूस के कार्यकाल के दौरान कट्टरपंथी युवकों के द्वारा काफी हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया गया, विशेषतौर से अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को हिंसा का शिकार बनाया गया, इस्कान के मुखिया को मारा गया, कई को गिरफ्तार किया गया और ऐसा लग रहा था कि बंगलादेश चुनाव में जनमत कट्टरपंथियों के साथ जायेगा। अब चुनाव के बाद बंगलादेश में बीएनपी बहुमत से सरकार में आई है और तारिक रहमान जो जिया उर रहमान के बेटे हैं, जिनकी माँ भी प्रधानमंत्री रही हैं, अब देश के प्रधानमंत्री बने हैं। उनकी सरकार के एक मंत्री जो हिंदू समुदाय से हैं, (चौधरी) ने सार्वजनिक रूप से बयान दिया है कि अल्पसंख्यकों को वैसे ही अधिकार होंगे जैसे बहुसंख्यकों को है। इस बयान के बाद अल्पसंख्यक समुदाय में उठ रही शंकाओं का कुछ हद तक हल हुआ और कुछ वातावरण भी बदला है। तारीक रहमान भी लगभग 18 वर्ष के निर्वासन के बाद विदेश से लौटे हैं। वह सुशिक्षित व्यक्ति हैं, अगर वे राजनीति को प्रतिहिंसा का माध्यम नहीं बनायेंगे तो यह उनकी बड़ी सफलता होगी। हालांकि अभी हिंसा, प्रतिहिंसा के बादल मौजूद हैं। बंगलादेश के चुनाव में शेख हसीना की पार्टी को चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया गया और यह एक प्रकार से एक दलीय चुनाव हुआ है। शेख हसीना की पार्टी वहां के चुनाव को रद्द करने की मांग कर रही है और यह आंदोलन बढ़ेगा, तो यह भी भारत के लिये एक समस्या बनेगा। बंगलादेश में श्रीमती हसीना के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं जिनमें उन्हें आजीवन कारावास और मृत्युदंड तक दिया जा सकता है। अभी तक बंगलादेश में हिंसा प्रतिहिंसा का चलन रहा है। बंगलादेश के जनक स्वरू शेख मुजीब की हत्या हुई उसके बाद जियाउर्र रहमान की हत्या हुई, उनकी पत्नी व रहमान को बाहर रहना पड़ा। मोहम्मद युनूस को बंगलादेश से निर्वासित किया गया। याने एक प्रकार से सत्ता के द्वारा प्रतिपक्ष व विरोधियों के दमन का जो सिलसिला शुरू हुआ है वह अभी थमा नहीं है। फिर तारिक रहमान उसे कैसे हल करेंगे, पुराने प्रतिहिंसा के रास्ते पर चलेंगे या उसे समाप्त करने के उपाय खोजेंगे यह कहना अभी संभव नहीं है। अपनी पीड़ाओं को भुलाकर अपने विरोधियों को माफ करना, सम्मान देना, यह लोकतांत्रिक तो है परंतु मानसिक रूप से आसान नहीं है। फिर शेख हसीना के हटने के बाद बंगलादेश व पाकिस्तान के बीच पुनरू याराना शुरू हुआ है। यद्यपि पूर्व स्थिति की बहाली तो संभव नहीं है परंतु मिलीजुली विदेश नीति भारत के लिये चुनौतियां खड़ी कर सकती है। शेख हसीना को बंगलादेश प्रत्यर्पित करने की मांग भी भारत व बंगलादेश के बीच एक टकराव का कारण बन सकती है। हालांकि अमेरिका के एक सीमित लक्ष्य की पूर्ति याने समर्थक और दोस्ती करने वाली सरकार हट गई है। पर अब यथास्थिति को बनाये रखने का उद्देश्य हो सकता है।

यद्यपि बालेन शाह ने कुछ शुरुआती निर्णय अच्छे किये हैं जैसे उन्होंने निजी शिक्षा बंदकर सारी शिक्षा को सरकारी करने की घोषणा की है। 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों की संपत्ति की जांच शुरू की है हालांकि उनका छात्र संघों के चुनावों पर रोक लगाने का निर्णय उचित नहीं है। छात्रसंघ चुनाव लोकतंत्र की पाठशाला होते हैं। और वे स्वतः भी छात्रों के आंदोलन के बाद ही चुनकर आये हैं। अमेरिका के लिये चीन समर्थक नेपाल मुफीद नहीं था और उससे मुक्ति पाने के लिये नेपाल में सत्ता परिवर्तन उसके अनुकूल है। फिर इन नये शासकों के चाहे बंगलादेश के तारिक रहमान हो, मोहम्मद युनूस हो, नेपाल के वीरेन्द्र शाह हो, इन सभी के के आर्थिक तार अमेरिका से जुड़े हुए हैं। वे सामान्य स्वभाव व आचार विचार से अमेरिका के अनुकूल ही रहेंगे। उनकी भूमिका एक प्रकार से अमेरिका के लिये उनके हितों के संरक्षक,पोषक ईरान के पूर्व शाह जैसी हो सकती है।

जेन जी या छात्रों के विद्रोह के नाम से जहां-जहां भी सत्ता परिवर्तन हुए हैं, उनके कोई अच्छे परिणाम नहीं निकले हैं और एक प्रकार से वे वैश्विक शक्तियों के हितों के टकराव के माध्यम व कारण सिद्ध हुए हैं। अब बंगलादेश व नेपाल में क्या वही दोहराव होगा या कोई नई राजनीति या वैचारिक भूमिका का उदय होगा यह कहना संभव नहीं है।

स्त्री सशक्तिकरण की बदलती भूमिका

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

स्त्री सशक्तिकरण के कथित स्थापित मानदंड पश्चिम बंगाल के 2026 के चुनाव परिणामों में टूटते दिखाई दिए हैं। इन परिणामों से जुड़ी तीन महिलाओं ने साबित कर दिया है कि स्त्री अस्मिता से जुड़े सुरक्षा के प्रश्नों का समाधान उच्च शिक्षा, उच्च पद या कार्पोरेट चकाचौंध करने वाली दीवारों के भीतर से नहीं, बल्कि स्वयं स्त्री के साहस, संघर्ष और आत्मचेतना के प्रखर आत्मबल से निकलेंगे। बीते कुछ समय में देखने में आया है कि एक वे महिलाएं हैं, जो उच्च शिक्षित और मजबूत आर्थिक स्वावलंबी होने के बावजूद कार्पोरेट बनाम धार्मिक जिहाद की शिकार बन गईं। हमें अशोक खरात के कथित अतींद्रिय-अलौकिक मायालोक से आसक्त होकर अपनी दैहित शुचिता गंवा बैठीं। जबकि विवाहित स्त्री के सम्मान और भरोसे का ही नहीं, सनातन मूल्य और संस्कार का भी यही सर्वाधिक प्रतिष्ठित गुण है। इन महिलाओं में महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष भी शामिल रही हैं। उच्च पद पर आसीन इस महिला का दायित्व था कि वह अंधविश्वास के पाखंड से महिलाओं को जागरूक व सचेत करती, जबकि वह खुद चमत्कार के आकर्षण में अपने चरित्र की पवित्रता खो बैठी। ऐसी ही जटिल स्थितियों के बीच बंगाल के विधानसभा चुनाव से तीन ऐसी महिलाओं की जीवटता देखने को मिली है, जो बड़े सामाजिक बदलाव का संदेश देती हैं।

बुलंद स्त्रियों की पहली आवाज है, संदेशखाली की रेखा पात्रा! यह वह साहसी महिला है, जिसने संदेशखाली में तृणमूल कांग्रेस नेताओं के यौन दुष्कर्म को झेला था। इन नेताओं के उत्पीड़न की हवस की रेखा अकेली षिकार नहीं थी, ज्यादातर युवा स्त्रियों को इन हवस के भूखे भेड़ियों ने अपना षिकार बनाया हुआ था। रेखा अपने मुख को घूंघट में छिपाकर बैठी नहीं रह गई, अपितु उसने घूंघट हटाकर संदेषखाली के बलात्कारियों के विरुद्ध मुख्य आवाज बन गई। मुख्य आरोपी शाहजहां शेख और उसके सहयोगी शिवप्रसाद हजारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। हजारी को इसी षिकायत पर गिरफ्तार भी किया गया था। यही वह शक्तिस्वरूपा रही, जो तृणमूल के नेताओं के विरुद्ध पीड़ित महिलाओं के समूह का नेतृत्व करते सड़क पर उतरी और आंदोलन का चेहरा बन गई। जब स्त्री के विद्रोह के स्वर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानों तक

पहुंचे तो उन्होंने रेखा से फोन पर बात कर 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बसीरहाट से उम्मीदवार बना दिया। वे हारीं जरूर, लेकिन उन्होंने आंदोलन के वातावरण को निरंतर गरम बनाए रखा। इस संघर्ष का परिणाम रहा कि उन्हें हिंगलगंज आरक्षित विधानसभा सीट से भाजपा ने उम्मीदवार बना दिया। अब वे विधायक हैं।

कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में एक महिला चिकित्सक की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। रत्ना देबनाथ ने बेटी के हत्यारों को सजा दिलाने का संकल्प तब लिया, जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कामकाजी स्त्री की मजबूरी को समझे बिना कह दिया था कि स्त्रियों को रात आठ बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ममता के इस बयान के बाद रत्ना बेटी के प्रतिकार की भावनात्मक प्रतीक बन कर न्याय के लिए जुट गईं। उन्हें जब समाज का सहयोग मिलने लग गया, तो उनमें राजनीतिक चेतना विकसित होने लग गई। तृणमूल नेता व कार्यकर्ताओं की धमकियों के भय से वे निर्भय हो गईं। 2025 में वे मजबूती से लड़ने के लिए भाजपा में सक्रिय राजनीति का हिस्सा बन गईं। तृणमूल द्वारा अपराधियों को खुला संरक्षण देने के चलते यह पहल जरूरी थी। यहीं उन्होंने शपथ ली, कि जब तक उनकी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, वे बालों में कंघी नहीं करेंगी। यह संकल्प द्रोपदी के द्वारा चीरहरण के बाद ली उस कसम की प्रतीक थी, जिसमें उन्होंने विद्वानों की भरी सभा में कहा था कि 'अब मैं अपनी चोटी तब तक नहीं बांधूगी जब तक दुशासन के लहू को बालों में नहीं डाल लूंगी।' रत्ना देबनाथ के इस संकल्प की ध्वनि मोदी के कानों में गूंजी और उन्हें पानीहाटी विधानसभा से उम्मीदवार बना दिया। इस पीड़िता के करुणा से आप्लवित स्वरों ने मतदाताओं को भीतर तक झकझोर दिया। फलतः उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को अट्ठाइस हजार से भी ज्यादा मतों से पराजित कर दिया।

एक और घरेलू कामकाजी महिला हैं, कलिता मांझी! चार घरों में काम करके परिवार चलाती हैं। भाजपा की मुखर समर्थक होने के कारण उन्हें तृणमूल कार्यकर्ताओं के नियमित उत्पीड़न का दंष झेलना पड़ा है। बावजूद वे दृढ़ता के साथ भाजपा के साथ दमदारी से जुड़ी रहीं। इसका प्रतिफल उन्हें औरग्राम आरक्षित सीट से भाजपा की उम्मीदवारी हासिल हो गई। उन्होंने तृणमूल के उम्मीदवार को 12 हजार से भी ज्यादा मतों से हरा दिया। इस महिला की जिजीविशा इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने गरीबी और उत्पीड़न की पीड़ा एक साथ झेलते हुए अपना राजनीतिक संघर्श अनवरत रखा।

इन तीनों महिलाओं की विपरीत परिस्थितियों में जीवटता देखते हुए कहना पड़ेगा कि उनकी ये उपलब्धियां केवल दलगत राजनीतिक षक्ति और संसाधन मिल जाने की सफलता नहीं है, बल्कि संकल्प सिद्धी की संजीवनी को स्वस्फूर्त अंतर-प्रेरणा से ऊर्जावान बनाए रखने के चलते मिली है। ये तीनों महिलाएं अलग-अलग पृष्ठभूमि से आती हैं, लेकिन सामाजिक बदलाव की भावना इनकी एक जैसी है। इनकी जीत ने तय कर दिया है कि अब मतदाता परंपरागत दलगत राजनीति की मानसिकता से मुक्त होकर उन चेहरों में उम्मीद तलाषने लगे हैं, जो संघर्श की जमीन से उपजीं और विपरीत परिस्थिति में खड़ी रहीं। अपनी राजनीतिक जमीन की बुनियाद पुख्ता करती रहीं। इनकी राजनीतिक उपलब्धियां, वंदनीय, अविस्मणीय एवं तक अनुकरणीय हैं।

दूसरी तरफ देष में ऐसी उच्च षिक्षित महिलाओं की श्रृंखला देखने में आ रही है, जो हर प्रकार से अर्थ व अधिकार संपन्न हैं। परंतु कार्पोरेट जिहाद का शिकार होकर मतांतरित होने को मजबूर हो गईं थीं। इस कड़ी में नासिक की टीसीएस कंपनी में कार्यरत इंजीनियर व एमबीए महिलाएं पदोन्नति, उत्तम अवसर के लालच में आकर इस्लामिक वेशभूषा, इबादत और रहन-सहन में ढलने लग गईं। सनातन संस्कारजन्य रीति-रिवाजों को बदलने लगीं। यहां तक की रोजे रखने लगीं, नमाज पढ़ने लगीं। इन तथ्यों की प्रामाणिकता एनआइए की जांच सीसीटीवी के फुटेज से तय हुई है। उच्च तकनीक में दक्ष ये महिलाएं मानसिक रूप से इतनी कमजोर और विचार के स्तर पर सतही साबित हुईं। ये कंपनी के मुस्लिम प्रबंधकों द्वारा इस्लाम धर्म के महिमामंडन के चलते उसकी गिरफ्त में आती चली गईं और धर्मांतरण करने को आतुर होती चली गईं। यह कारपोरेट जिहाद हिंदुओं की अस्मिता के समक्ष ऐसी चुनौती बनकर उभरा है, जिससे सामान्य परिस्थितियों में निपटना आसान नहीं है ?

एक वे महिलाएं हैं, जो कथित ढोंगी अशोक खरात के फरेब में आकर स्वेच्छा से शारीरिक संबंध बनाने को तैयार हो जाती हैं। ये सब महिलाएं विवाहित प्रौढ़ाएं हैं। आईएएस, आईपीएस और राजनेताओं की पत्नियां हैं। ये इस स्वयंभू धर्मगुरु के चंगुल में फंसती चली गईं। यहां तक की महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर इसके चंगुल में आ गईं। उत्तम शिक्षा और उच्च पद की प्राप्ति के बाद ऐसी महिलाओं से उम्मीद तो यही की जाती है कि ये किसी भी शोषण और अन्याय के विरुद्ध अपनी वाणी को बुलंद करेंगी। उजले चेहरों को बेनकाब करेंगी? उनका घिनौना चरित्र उजागर करेंगी ? लेकिन देखने में आया कि धर्मांतरण और अंधविश्वास के लिए यौन शोषण के लिए भी समर्पित दिखाई दीं। अभी तक हम यह सुनते चले आ रहे थे कि फिल्मों में काम पाने के लिए अभिनेत्रियां अपना शरीर निर्माता-निर्देशकों को सहज रूप में सौंप देती हैं। राजनीति में भी यह स्थिति बनती रही है। कुछ फिल्मी पर्दे की नायिकाओं ने इस दुराचार का 'मी-टू' अर्थात 'मैं भी बोलूंगी' के बहाने 2018 में कुछ नायिकाएं मुखर भी हुईं। लेकिन उन्होंने यह सब संबंध बनाने के पूर्व नहीं, बल्कि लाभ उठाने के बाद किया। इन बयानों को कथित प्रगतिशीलों ने परिवर्तन की भूख माना तो कुछ ने इस मी-टू को उपभोक्तावादी संस्कृति का मसालेदार हिस्सा माना। अब कार्पोरेट जिहाद और पाखंडी ढोंगी के समक्ष अर्थ-संपन्न, अनुभवजन्य प्रौढ़ाओं के समर्पण को हम क्या मानें? क्या कहें? नौकरी बचाए रखने की लालसा या कथित 'योनि-पूजा' के बहाने उत्कट भोग की तीव्र उत्कंठा?

दूसरी तरफ हमारे सामने रेखा पात्रा जैसी वह स्त्री है, जो अपने साथ हुए दुष्कर्म के विरुद्ध आवाज उठाती है, बल्कि दोशियों को कानून के कठघरे में ला खड़ा करती है। वह बहुत ज्यादा पढ़ी-लिखी नहीं है, लेकिन देह की पवित्रता और संस्कारों की मर्यादाओं को बखूबी जानती है। वह उस प्रचलित मिथक से मुक्त होती है कि बलात्कारी ने उसका 'सब-कुछ' लूट लिया? वह समाज की इस मान्यता को भी परे धकेलती है कि लूटी गई आबरू कभी बहाल नहीं होती? क्योंकि स्त्री का जननांग ऐसा अंग है, जो अवैध शारीरिक संबंध हों या जबरन बलात्कार, उसकी दैहिक शुचिता हमेशा-हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। हालांकि अब यह अच्छी बात है कि यौन-शुचिता के मूल्यबोध का भ्रम खंडित हो रहा है। अब समाज न केवल लव जिहाद के संकट से गुजरी महिलाओं को स्वीकार रहा है, बल्कि कार्पोरेट जिहाद, मतांतरण और अंधविश्वास के पाखंड की शिकार हो चुकी महिलाओं के लिए भी न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। उत्पीड़ित स्त्रियों को सम्मान उचित है, लेकिन इन स्थितियों से स्त्रियों और उनके परिजनों को सचेत रहने की जरूरत है।

गौहत्या, चोरी और संदिग्ध मौत को लेकर कांग्रेस का थाने पर धरना, पुलिस पर फूटा आक्रोश

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरनी। नगर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं, गौहत्या और संदिग्ध मौत के मामलों को लेकर कांग्रेस ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहन साई, विधायक अभिजीत शाह और नगर कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष जायसवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सूर्या टावर से रैली निकालकर थाने का घेराव किया और करीब एक घंटे तक कड़ी धूप में धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेसी जमीन पर बैठकर विरोध जताते रहे और "पुलिस प्रशासन हाय-हाय" व "गौमाता के हत्यारों को गिरफ्तार करो" जैसे नारे लगाए। धरने के दौरान नेताओं ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि नगर में कानून व्यवस्था पूरी तरह

चरमरा गई है। पिछले चार महीनों में एक दर्जन से अधिक चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन अब तक एक भी आरोपी गिरफ्त में नहीं आया है। वहीं अवैध शराब, जुआ-सट्टा और ड्रग्स का कारोबार खुलेआम चलने का आरोप भी लगाया गया। विधायक अभिजीत शाह ने एसडीओपी आकांक्षा तलैया से सीधे सवाल करते हुए कहा कि- क्या पुलिस गौहत्या मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगाल पाई? क्या रामदास कोरकू को बिना ठोस सबूत के थाने में घंटों बैठाया गया? अगर थाने में जहर खाने की घटना हुई, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस "अंधेरे में तीर" चला रही है और निर्दोष लोगों को प्रताड़ित कर रही है। चेतावनी दी कि यदि हालात नहीं सुधरे तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

कार्बन संकटः अस्तित्व का अंतिम मौका

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद

कल्पना कीजिए, आपकी साँसें धीरे-धीरे रुक रही हैं, हर साल 50 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में जहर घोल रहा है। "कार्बन संकटः अस्तित्व का अंतिम मौका" यह सिर्फ़ शीर्षक नहीं, बल्कि हमारी धरती का SOS है। अगर हम अभी उत्सर्जन नहीं रोके तो 2050 तक वैश्विक तापमान 2 डिग्री ऊपर पहुँच जाएगा। बाढ़, सूखा और विलुप्ति की लहरें सब कुछ निगल लेंगी। क्या हम इंतजार करेंगे या कार्रवाई करेंगे? जीवाश्म ईंधन से वैश्वीकरण कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन पूर्व की तुलना में एक फीसदी बढ़ने का अनुमान है जो खतरे की घंटी है और इसे बढ़ने से रोकना ही एक विकल्प है। बीते दशक में किसी भी देश ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने की उतनी प्रयास नहीं की जितनी अपेक्षा थी। चिंता इस बात की है कि कार्बन उत्सर्जन की वृद्धि की यही रफ्तार रही तो आने वाले कुछ वर्षों में औद्योगिक पूर्व तापमान से 1.5 डिग्री सेल्सियस से उपर पहुंच जाएगा जो दुनिया के लिए एक चुनौती होगा। पिछले कुछ दशकों से मानवजनित गतिविधियों के चलते कार्बन डायऑक्साइड और दूसरे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन प्रतिवर्ष 1 फीसदी की दर से बढ़ा है। इससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा हमारे पर्यावरण को लगातर नुकसान पहुंचा रहा है जबकि दुनिया के अस्तित्व के लिए के लिए कार्बन उत्सर्जन को कम से कम प्रतिवर्ष 3-6 फीसदी की दर कम करना होगा जिससे धरती के बढ़ते तापमान पर अंकुश लगाई जा सके। हालाकि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के दौरान इसके सदस्यों देशों ने धरती के तापमान को इस शताब्दी के अंत तक 2 डिग्री सेल्सियस कम करने का संकल्प लिया था लेकिन इसे लागू होने के आठ साल के बाद भी इस दिशा में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। संप्रभु देशों में साल 2050 तक कार्बन उत्सर्जन के स्तर को शून्य करने की प्रतिबद्धता दोहराई थी। चिंता की बात यह है कि कार्बन उत्सर्जन को लेकर शिखर सम्मेलन, सेमिनार और बैठकों के दौर भले ही कितने मजबूती के साथ होते रहे हों, लेकिन इस मामले में लगाम लगाना तो दूर की बात है, इसका स्वरूप लगातार घातक रूप धारण करता जा रहा है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने यहां पर्यावरण नीति तक को लागू नहीं किया है। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून ने ऊर्जा को लेकर कहा था कि यह "सोने का वो धागा है जो आर्थिक विकास, सामाजिक समानता और पर्यावरणीय स्थिरता को जोड़ता है"।

इसका मूल कारण कोयले की खपत में बेतहाशा बढ़ोतरी है। यह बढ़ोतरी तेल की खपत में भी हुई है। भारत भी इस मामले में पीछे नहीं है। भारत में साल 2022 में उत्सर्जन में छह फीसद की वृद्धि हुई है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण कोयले का इस्तेमाल रहा। हालाकि कार्बन डायऑक्साइड के बढ़ते स्तर से भारत पर क्या प्रभाव होगा इसका कोई आकलन नहीं है। सेंटर फॉर साइंस द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार 20वीं सदी की शुरुआत के बाद भारत के वार्षिक औसत तापमान में लगभग 1.2 डिग्री की वृद्धि हो चुकी है जिसके परिणामस्वरूप मौसम की घटनाओं जैसे बेमौसम बारिश, बाढ़, सुखा, और उसमें आ रही अनियमितता और ओलावृष्टि मे हो रही वृद्धि साफ देखी जा सकती है। कार्बन उत्सर्जन की वृद्धि अमेरिका सहित बाकी दुनिया में भी रही, मगर तुलनात्मक फीसद कम है, जबकि चीन और यूरोपीय संघ में 2021 में मुकाबले क्रमश 0.9 व 0.8 फीसद की गिरावट दर्ज की गई। दुनिया के दस सबसे बड़े कार्बन डायऑक्साइड का उत्पादक देशों का कुल कार्बन डायऑक्साइड गैस के उत्पादन में 67.6 का योगदान है, जिसमे चीन का अकेले योगदान लगभग 30% है। हालाकि भारत ने संयुक्त राष्ट्र को आश्वस्त किया है कि 2070 तक नेट शून्य तक पहुंचने के और 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पादों की संबद्धता को 45 प्रतिशत तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। दावे कुछ भी करें लेकिन असलियत में सौर उर्जा और पवन उर्जा के मामले में हम बहुत पीछे हैं जबकि इस क्षेत्र में हमे बहुत आगे होना चाहिए था। इस दिशा में यूरोप की प्रशंसा की जानी चाहिए जिसने अक्षय उर्जा के महत्व को समय रहते समझ लिया। साल 2000 के दशक के शुरुआत में यूरोप में कार्बन उत्सर्जन की वृद्धि की दर तीन फीसदी सलाना थी लेकिन इस साल को एक फीसदी की अनुमानित बढ़ोतरी अपेक्षाकृत कम ही है। कॉप 26 की बैठक में 193 देशों ने राष्ट्रीय कारवाई योजनाओं को अधिक महत्तवपूर्ण बनाने शून्य उत्सर्जन, वन संरक्षण और जलवायु वित्त पोषण सहित अनेक संकल्प लिए थे लेकिन दुख की बात यह है कि अभी तक कुछ ही देशों ने ही यू एन को अपनी योजनाएं भेजी है। ऐसी स्थिति में धरातल पर पूर्ण, समावेशी, सामायिक व विस्तृत कारवाई की उम्मीद बेमानी है। जलवायु से जुड़े मुद्दों पर कुछ भौतिक दृष्टिकोण को लेकर विचारों से भिन्नता के कारण प्रमुख मुद्दों पर प्रगति की जो आशा थी वह भूमिल तो हुई है लेकिन 150 से अधिक देश मीथेन उत्सर्जन को कम करने के सवाल पर सहमत हुए हैं।

जहां तक भारत का प्रश्न है भारत के सामने दोहरी चुनौती है। एक तो यहां करोड़ों लोग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे हैं। इन्हें गरीबी से बाहर निकालने के लिए आर्थिक विकास जरूरी है। दूसरी तरफ ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन पर लगाम लगाना है। ये दोनों लक्ष्य अपने आप में विरोधाभासी हैं। भारत को जलवायु परिवर्तनों के प्रभाव को कम करने और वित्तीय आवश्यकताओं के लिए धनी देशों पर दबाव बनाए रखना चाहिए। भारत ने ग्लोबल वार्मिंग में बहुत कम योगदान दिया है और दुनिया की आबादी का 17 प्रतिशत हिस्सा मौजूद होने के बावजूद, संचयी वैश्विक जीएचजी उत्सर्जन में इसका ऐतिहासिक योगदान बहुत कम रहा है। भारत को जलवायु सहनशील होने की जरूरत है। राष्ट्रीय परिस्थितियों के आलोक में, समानता, साझा एवं अलग-अलग जिम्मेदारियों और सम्बन्धित क्षमताओं (सीबीडीआर-आरसी) के सिद्धांतों के साथ-साथ "जलवायु न्याय" और "स्थायी जीवन शैली" के दो विषय, जिन पर भारत ने पेरिस में जोर दिया था, कम उत्सर्जन वाले भविष्य के केंद्र में है।

कार्बन उत्सर्जन में 45% कटौती संभव है- नवीकरणीय ऊर्जा, वनों की रक्षा और नीतिगत बदलाव से। सरकारें, कंपनियाँ और हम हर नागरिक- सबका योगदान मायने रखता है। आज वादा कीजिएः एक पेड़ लगाएँ, प्लास्टिक कम करें, आवाज़ उठाएँ। अस्तित्व का अंतिम मौका हमारे हाथ में है। इसे व्यर्थ न जाने दें, धरती को नई ज़िंदगी दें।

मदर्स-डे पर विशेष

मेरी जमाने में जो शोहरत है वह मेरी मां की बदौलत

आज की बात

प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

माँ, वह हस्ती जिसके आगे दुनिया की हर दौलत फीकी है, जिसके चरणों में जन्नत है। पश्चिम ने भले ही 'मदर्स डे' की नींव रखी हो, लेकिन हमारी संस्कृति तो युगों से हर दिन को माँ का ही मानती आई है। जिसने नौ महीने अपनी साँसों से मेरी साँसों को बुना, जिसने अपने सपनों को मेरे सपनों के लिए कुर्बान कर दिया, उस माँ के लिए साल का केवल एक दिन समर्पित करना? यह तो उस अथाह सागर को एक बूंद में समेटने जैसा है। नहीं, माँ के लिए तो हर पल, हर धड़कन, हर साँस उसी की अनमोल देन है। फिर भी, आज का यह दिन एक सुंदर अवसर है, उन ममतामयी आँखों को याद करने का और उस असीम ममता के आगे अपना शीश झुकाने का, जिसके आगे संसार की हर वैभव फीका पड़ जाता है। आइए, इस मदर्स डे पर हम उस दिव्य शक्ति को याद करें जो हमारे जीवन का आधार है।

मां के आशीष को शब्दों में पिरोना नामुमकिन है लेकिन बस इतना कह सकता हूं कि मेरी जमाने में जो शोहरत है वह मेरी मां की बदौलत है। आज मदर्स डे है, मैं उस हर मां के संघर्ष को याद कर रहा हूं जिसने ना जाने कितने दुख उठाकर अपने बच्चों की परवरिश की और उन्हें समाज में एक पहचान दिलाई। मैं अपनी हर गहरी भावना में अपनी मां को महसूस कर पाता हूं। अथाह ममता और प्यार को सराहने का दिन है। तुम्हारे महत्व को शब्दों में बाँधना तो असंभव है, माँ। तुम्हें परिभाषित करने के लिए तो दुनिया के सारे शब्द भी कम पड़ जाएँ।

जिसके लबों पर कभी बद्दुआ नहीं होती,
बस एक माँ ही है, जो कभी खफा नहीं होती।

हमारे भारत में तो एक नहीं, दो-दो बार नवदुर्गा का पर्व आता है और पूरा देश सर्वशक्तिमान माँ की आराधना में डूबा रहता है। हम तो अपने देश को भी भारत माता कहते हैं और उसके सम्मान को सर्वोपरी रखते हैं। हमें जन्म देने वाली माता के प्रति हमारा सर हमेशा श्रद्धा से झुंकता है। जो परंपरा भारत में अनादिकाल से चली आ रही है, उसे यूरोप और अमेरिका तक पहुँचने में सदियाँ लग गईं। इसलिए सबसे पहली बार अमेरिका में 1908 में अमेरिकन एक्टिविस्ट एना जार्विस ने मदर्स डे की शुरुआत की। हम भारतीय किसी भी पर्व, किसी भी उत्सव, किसी भी परंपरा को कभी खारिज नहीं करते। हमारी संस्कृति ने हमेशा अच्छी परंपराओं और अच्छे विचारों का खुले दिल से स्वागत किया है। इसीलिए जब मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे या मातृ दिवस मनाने का प्रचलन भारत में पहुँचा, तो भारत के निवासियों ने इसे सहजता से स्वीकार कर लिया। उनके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, बल्कि एक स्वाभाविक परंपरा के रूप में उन्होंने इसे अपने जीवन में अपना लिया।

माँ, वह शक्ति है जो धूप में तपती साड़ी के पल्ले को छाँव बनकर अपने बच्चों को झुलसने से बचाती है, तो कभी ईंटों के बोझ तले दबी अपनी कमर को सहलाते हुए भी बच्चों का पेट पालती है। वह स्वयं भूखी रहकर भी अपने बच्चों के थाल को स्वादिष्ट व्यंजनों से भर देती है। माँ का प्रेम का आंचल हमेशा अपने बच्चों पर छाया रहता है, हर मुश्किल और संघर्ष को सहकर भी वह उनकी बेहतरीन परवरिश करती है। माँ के दिए हुए अनमोल संस्कार ही तो हैं, जो बच्चों के चरित्र में आजीवन सुरक्षित रहते हैं।

माँ का आशीर्वाद मेरे साथ चलता है

मेरी प्यारी माँ,
विद्या देवी कक्कड़,
तुम्हें इस दुनिया से गए करीब साढ़े नौ साल हो गए, पर एक पल भी ऐसा नहीं लगता कि तुम मुझसे दूर हो। तुम्हारे चले जाने के बाद भी, तुम्हारा आशीर्वाद भावनात्मक रूप से हर पल मेरे साथ है। माँ, तुम्हारा साथ होना जीवन का सबसे सुखद अनुभव था। तुम्हारा स्पर्श अमृत के समान था। जीवन के हर उतार-चढ़ाव और चुनौतियों में, जब तुम्हारा हाथ मेरी पीठ पर होता था, तो बड़ी से बड़ी लड़ाई भी जीतने की ताकत आ जाती थी। आज समाज में जो थोड़ी बहुत मेरी प्रतिष्ठा है, मेरे प्रयासों को जो थोड़ी बहुत सराहना मिलती है, या जो पुरस्कार और सम्मान मुझे मिले हैं, वह सब तो माँ, तुम्हारे आशीर्वाद और तुम्हारे अटूट विश्वास का ही फल है। आज मदर्स डे पर तुम्हें याद करते हुए, तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल मेरी आँखों के सामने जीवंत हो उठता है। मेरे व्यक्तित्व, मेरे स्वभाव, मेरी शिक्षा और दुनिया के ज्ञान में अगर किसी का सबसे ज्यादा असर है, तो वह सिर्फ और सिर्फ तुम हो, माँ। तुम्हारे चले जाने के बाद भी, तुम्हारा आशीर्वाद एक अदृश्य शक्ति बनकर हमेशा मेरे साथ है।

दीनदयाल उपाध्याय
भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

4.95 लाख से अधिक हितग्राहियों के बैंक खाते में
₹495.96 करोड़
आदान राशि अंतरित

बजट 2026-27 में **₹600 करोड़** का प्रावधान

भूमिहीन कृषि मजदूरों को दी जा रही **₹10,000 प्रति वर्ष** की आर्थिक सहायता

वर्ष 2025 में **5.62 लाख** से अधिक हितग्राहियों के खातों में **₹562.11 करोड़** से अधिक की राशि अंतरित

22,028 बैगा-गुनिया परिवारों को भी मिल रहा लाभ

साय सरकार में मेहनतकश हाथों को मिल रहा संबल, सुरक्षा और सम्मान

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क | Visit us : /ChhattisgarhCMO /DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

R.O. No. : 13769/ 2

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। **संपादक : विजया पाठक।**
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)